जोखिम प्रबंधन: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकताएं *

उषा थोरात

भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इस सहस्राब्दी का नया दशक पहले दशक की तुलना में अधिक परिवर्तनकारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। यदि पिछले दस वर्षों में लगातार उच्च वृद्धि दर, कोर बैंकिंग समाधान अपनाने, भुगतान प्रणाली में परिवर्तन और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण के संदर्भ में परिवर्तन देखा गया, तो आने वाले दशक में भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए व्यवसाय की अभूतपूर्व मात्रा दिखेगी क्योंकि यह तेज और समावेशक वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) ने बैंकों के लिएयह संभव किया है कि वे बड़ी संख्या में व्यवहार कर सकें और मात्रा तथा मूल्य में इस तरह की वृद्धि से स्पष्ट रूप से जोखिम प्रबंधन की भारी चुनौतियां सामने आएंगी जो नए व्यवहारों के संदर्भ में मानव संसाधनों और आईटी पर निर्भर करेंगे जो कि इस सम्मेलन के लिए उपयुक्त विषय है।

2. स्पष्ट रूप से, प्रमुख चुनौती सही प्रकार और संख्या का मानव संसाधन होने और कुशल कर्मियों को बनाए रखने की है। सर्वाधिक गरीबों को बैंकिंग सेवाएं देने वाले कर्मी होना, परिष्कृत वित्तीय उत्पाद देने की विशेषज्ञता होना और संगठन में लगातार जोखिम प्रबंधन की प्रथाओं को अपनाना विशाल संगठनों के बेहतर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

3. वैश्विक वित्तीय संकट का एक कारण यदि यह था कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र से अलग प्रकार से विकसित हुआ था, तो भारत में स्थिति में इस प्रकार से भिन्न है कि वित्तीय प्रणाली को यह सुनिश्चित करना है कि वह बढ़ते वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करें। बैंकिंग में जोखिम निहित होती है क्योंकि बैंक परिपक्वता परिवर्तन की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से जोखिम में व्यापार करते हैं। इसलिए बैंक जोखिम बच नहीं सकते। उसी समय 'बैंकर का विवेक जमाकर्ताओं

* मुंबई में 12 जनवरी 2010 को आयोजित 'बीएएनसीओएन - भारतीय बैंकिंग सभा 2009-10' में अध्यक्षता करते हुए श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'जोखिम प्रबंधन: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकताएं' पर पैनल चर्चा में दिया गया प्रारंभिक भाषण।

धन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है' हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जोखिम-वापसी संबंध को परिणाम को कल्याणकारी बनाने के लिए अधिकतम संतुलित होना चाहिए।

4. इस संकट ने जोखिम प्रबंधन नीतियों संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक मुद्दों को सामने लाया है:

- व्यापार मॉडल के मुद्दे। ट्रेडिंग बुक्स में अति सक्रिय रहे बैंक स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावित थे। अधिक परंपरागत बैंकिंग वाले बैंक कम प्रभावित थे।
- जोखिम के प्रति सहज ज्ञान युक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। लाभ में भारी वृद्धि और 'तुलनपत्र की' और 'तुलनपत्रेतर' मदों में भारी विस्तार होने के बावजूद, जटिल जोखिम मॉडलों ने जोखिम के उन प्रयासों को दूर कर दिया जो अवशोषण में काफी सक्षम प्रतीत होते थे। इन मॉडलों के लिए एक स्पष्ट सीमा थी, विशेष रूप तनाव के समय में। यह अपर्याप्तता दो दृष्टिकोण से दिखी -
  - क. तनाव की गंभीर अवधि के आंकड़ों में पर्याप्त रूप से विश्लेषण के बिना पिछले आंकड़ों का प्रयोग और
  - ख. यह अनुमान कि अत्यधिक परिष्कृत गणितीय मॉडल उतने ही सफल होंगे जितने वे भौतिक विज्ञान में हैं।

बाद का अनुमान स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि वित्तीय घटनाएं बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित या तर्कहीन मानव व्यवहार से प्रभावित होती हैं जिसे कोई मॉडल पकड़ नहीं सकता। फिर भी, ये तब उपयोगी हैं जब इन्हें तनाव / परिदृश्य-विश्लेषण और सूचित निर्णय से आपूरित निविष्टि के रूप में माना जाता है। एक अन्य गंभीर चिंता का कारण बनने वाला मुद्दा इन मॉडलों का बोध सहातकों के एक छोटे समूह तक सीमित रहता है और संगठन द्वारा उठाई गई वास्तविक जोखिम को समझना शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सबकों को अब ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि कुछ बैंक उन्नत तरीकों की ओर कदम बढ़ाएंगे।

- जोखिम का मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण है। चलनिधि की अधिकता और लाभ उत्पन्न करने के दबाव के समय जोखिम को कम आंकने की इच्छा होती है। लागत से कम मूल्य निर्धारण जोखिम भरा है और जोखिम लागत कई बार पर्याप्त रूप से पकड़ में नहीं आती है। इसके अलावा, यह विद्यमान प्रभाव के साथ आस्ति मूल्य बुलबुले बढ़ते हैं।
- जबकि ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम को पिलर I और बासल II के तहत पूंजी ढांचे में रखा जाता है, वहीं चलनिधि जोखिम, संकेंद्रन जोखिम, रणनीतिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम और प्रतिभूतीकरण, तुलनपत्रेतर माध्यमों, मूल्यांकन प्रथाओं से उत्पन्न जोखिम को पहचानने की आवश्यकता है। बैंकों के बोर्डों के लिए इस बात की जरूरत है कि वे इन सभी जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करें और बैंकों की गतिविधियों के प्रासंगिक मुख्य जोखिमों पर सीमा निर्धारित करें। बैंकों को मजबूत तनाव परीक्षण पर ध्यान देना चाहिए। मुआवजा पैकेज भी जोखिम प्रबंधन नीतियों का हिस्सा होना चाहिए।
- इस संकट ने आंतरिक नियंत्रण, अच्छे कंपनी संचालन और जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया है। जोखिम प्रबंधन पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक समूह की रिपोर्ट में दिखाए अनुसार, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों वाले कुछ बैंकों ने मौजूदा संकट का सामना बहुत से ऐसे बैंकों की तुलना में बेहतर रूप से किया जिनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां मजबूत या पर्याप्त नहीं थीं।

- उन बैंकों के लिए जो वित्तीय संगुट का हिस्सा हैं, जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में अंतर-समूह एक्सपोजर और लेनदेन कए साथ ही क्षेत्रों और उधारकर्ताओं के समूहवार एक्सपोजर पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

- इस संकट में पहचाना गया नया तत्व यह है कि फर्म स्तर पर देखी गई मजबूत जोखिम प्रबंधन नीतियों के बावजूद प्रणालीगत जोखिम की संभावना हो सकती है जिसपर बैंकों कोई नियंत्रण नहीं है और यहां प्रणालीगत स्तर पर इस जोखिम प्रबंधन आवश्यक हो जाता है - अर्थात वित्तीय नियामकों और नीति निर्माताओं द्वारा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।

5. मैं अब प्रमुख क्षेत्रों पर आना चाहूंगी जहां बैंकों को उच्च वृद्धि के लिए ऑन गोइंग अंतरराष्ट्रीय नियामक पहलों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार की योजना बनाते समय ध्यान केंद्रित करना होगा। बेसल समिति ने 17 दिसंबर 2009 को दो परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किए जिनमें मुख्य प्रस्ताव दिए गए हैं जिन्हें अपनाने से पहले उनका प्रभाव-अध्ययन किया जाएगा। इन प्रस्तावों में पूंजी की बढ़ती गुणवत्ता और कवरेज को कवर किया गया है ताकि निम्न बातों को सुनिश्चित किया जा सके - हानि अवशोषणता को चालू और समाप्त आधार पर, टियर-I और आम इक्विटी घटक पर अधिक दबाव, लिवरेज अनुपात की शुरूआत, पूंजी बफर और भावी प्रावधानजैसे चक्रीयता समर्थकता का सामना किया जा सके, न्यूनतम चलनिधि और पुस्तक प्रतिभूतीकरण व्यापार के लिए विस्तारित पूंजी और प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की शुरूआत।

6. जबकि हमारा आकलन है कि भारतीय बैंक आम तौर पर इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे, किसी कच्चे और तैयार आधार पर यह देखना उपयोगी होगा कि इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है। हमारा आकलन दिखाता है कि:

- कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में आम इक्विटी घटक मार्च 2009 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए 7 प्रतिशत था जबकि बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए यह 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में था। कुल सीआरएआर 13.75 प्रतिशत और टीयर 1 9.4 था। इस प्रकार, भारतीय बैंक वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में हैं और भावी वृद्धि के लिए योजना बनाने और अपेक्षित पूंजी जुटाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है।

- भारतीय बैंकों के लिए लिवरेज अनुपात (तुलनपत्रेतर के ऋण समतुल्यों सहित) मार्च 2009 में 17 प्रतिशत था और इसे उचित माना जा सकता है।

- जबकि एसएलआर की स्थिति अच्छी थी, प्रस्तावित अल्पकालिक चलनिधि कवरेज अनुपात और दीर्घावधि निवल स्थिर निधीयन अनुपात जैसे सलाहकारी दस्तावेज़ में रखे गए अधिक स्तरबद्ध चलनिधि अनुपातों के प्रति बैंक अपनी चलनिधि जोखिम का मूल्यांकन ठीक से करेंगे। यह कार्य बैंकों के लिए नियमित स्वरूप का होना चाहिए जिनका जमाराशि और जमाराशि प्रमाणपत्र में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

- भावी प्रावधानीकरण के बासेल प्रस्ताव विकसित दृष्टिकोणों पर आधारित हैं जो सायकल पीडी आदि के माध्यम से प्रयोग किए गए हैं। भारत में, बैंकों ने अभी तक विकसित दृष्टिकोणों को नहीं अपनाया है। बैंकिंग क्षेत्र का सकल एनपीए 31 मार्च 2008 के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 30 सितंबर 2009 को 2.6 प्रतिशत हो गया। बढ़ते एनपीए और पुनर्गठित खातों में गिरावट की संभावना के संदर्भ में, हमने भावी अपेक्षा के रूप में एनपीए के लिए 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात शुरू किया था। अधिकांश बैंक वर्तमान में इस अनुपात पर पहुंच गए हैं। मानक

आस्तियों के लिए, भावी प्रावधानीकरण के लिए बासेल प्रस्तावों के अनुरूप स्पेनिश गतिशील प्रावधानीकरण मॉडल के आधार पर अनुमानित हानि की माप और क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के आधार पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

- व्यापार पुस्तक और प्रतिपक्षी जोखिम के लिए पूंजी के मामले में, जबकि विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के लिए कुछ विस्तार किया गया है, प्रतिपक्षी जोखिम और अन्य डेरिवेटिव के लिए अधिक कार्य आवश्यक हो जाएगा। फिर भी, मात्र व्यापार पुस्तक के बजाय पूरे तुलनपत्र के लिए ब्याज दर जोखिम को देखना ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है।

7. अब मैं उन क्षेत्रों पर आना चाहूँगी जहां बैंकों को जोखिम के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यता है:

- जबकि समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि चालू वर्ष में धीमी रही है, भूसंपदा, बुनियादी संरचना और एनबीएफसी जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि की अधिक दर देखी गई। वाणिज्यिक भूसंपदा को ऋण सितंबर 2009 को समाप्त छमाही में कम हो गया जो अधिक जोखिम धारणा दर्शाता है। किंतु, एनबीएफसी और बुनियादी संरचना को ऋण लगातार अधिक बना रहा। जबकि देश के लिए भारी पैमाने पर बुनियादी संरचना के वित्तपोषण की आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से अल्पावधि संसाधन जुटाने वाले बैंक एएलएम, व्यापक एक्सपोजर और कार्यान्वयन बाधाओं जैसी नियंत्रण से बाहर की कुछ जोखिमों के कारण बैंकों को जोखिम का सामना करना पड़ता है। पेंशन और बीमा निधि, कंपनी बॉंड बाजार का विकास और एकल नाम की सी डी एस जैसे दीर्घावधि निवेशकों के उभरने से बुनियादी संरचना के प्रति बैंकों के एक्सपोजर में कुछ कमी आ सकती है।
- भारिबैं ने हाल ही में बैंकों के ध्यान में जो बात लाई वह थी बैंकों द्वारा ऋणमुखी पारस्परिक निधियों में भारी निवेश। पारस्परिक निधियों ने भारी राशि का निवेश बैंकों के जमा प्रमाणपत्रों में किया है। जिन बैंकों की देयताओं का महत्वपूर्ण भाग जमा प्रमाणपत्रों के रूप में है उन्होंने रोलओवर जोखिम के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वैसे ही, पारस्पारिक निधियों में भारी निवेश वाले बैंकों ने बड़े निवेशकों द्वारा उसी समय अचानक शोधन करने की आवश्यकता की स्थिति में चलनिधि जोखिम के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस विरूपण - जिसके द्वारा पारस्परिक निधियां स्पष्टतः मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं जहां अन्यथा अंतर बैंक बाजार ने मध्यस्थता की होती - पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पारस्परिक निधि मध्यस्थता के माध्यम से संसाधन प्रवाह की दिशा के बारे में चिंता है।
- व्यष्टि वित्त में लगी हुई एनबीएफसी को दिए गए उधार को बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के रूप में मानने के मामले में, यह जोखिम है कि बहुविध उधार और उच्च ब्याज दरों से आस्ति गुणवत्ता पर बुरा असर हो सकता है। इन ऋणों के निर्माताओं का इनमें जोखिम न होने से बैंक नमूना आधार पर जमीनी स्तर पर बेहतर निगरानी से इन ऋणों की ऋण गुणवत्ता का अच्छा मूल्यांकन कर पाएंगे।
- जबकि बैंक अपने परिचालनों को विविधतापूर्ण बना रहे हैं और नए व्यवसाय में हैं, यह जरूरी है कि प्रतिष्ठा जोखिम की पहचान की जाए, खासकर जब वीसीएफ और अन्य ऐसी निधियों को बढ़ावा दिया जा रहा हो। जैसा कि अब इसे अच्छी तरह से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बैंकों ने पहले कुछ मदों को उनके बैलेंस शीट से हटाकर विशेष निवेश माध्यमों में रखा था। बाजार तंगी के समय

बैंकों को उन आस्तियों को पुन: अपने तुलनपत्रों पर लेना पड़ा था।

- बैंकों द्वारा आस्तियों का 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया प्रतिभूतीकरण पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। यह बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है जो प्रतिभूतीकरण कार्य को एक मुख्य व्यवसाय लाइन के रूप में कर रहे हैं। किंतु, खुदरा ऋण घटक में पुन: वृद्धि प्रारंभ होने पर प्रतिभूतीकरण गतिविधियां पुन: बढ़ सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही प्रतिभूतीकरण योग्य ऋण के लिए न्यूनतम रोक अपेक्षा और न्यूनतम धारण अवधि पर दिशानिर्देश जारी करेगा।
- जबकि प्रतिरक्षा या शेष अप्रतिरक्षित उधारकर्ताओं के विशेषाधिकार हैं, बैंकों को यह याद रखना चाहिए कि उनके उधारकर्ताओं की अप्रतिरक्षित स्थिति से उनकी आस्ति गुणवत्ता पर शीघ्र ही गंभीर दबाव आ सकता है और इसलिए यह बिल्कुल जरूरी है कि कंपनियों की अप्रतिरक्षित स्थिति की बारीकी से निगरानी की जाए और उन्हें सुविधाएं देते समय ये उधारकर्ताओं के ऋण और अन्य रेटिंग मूल्यांकन में बदल जाएं।
- प्रणाली में अत्यधिक चलनिधि से एक बार फिर उप पीएलआर अल्पावधि उधार की सामान्य स्थिति बन गई; बैंक पुनर्मूल्यन और रोलओवर जोखिम ठीक से पहचान पाएंगे।
- ऋण सूचना अंतर मिटाने के लिए भारिबैं ने चार ऋण सूचना कंपनियों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक प्राधिकरण जारी करके दीर्घावधि उपाए किए हैं। इसे परिचालन में आने के लिए कुछ समय लगेगा। किंतु इस बात को पहचानना होगा कि यह प्रणाली जानकारी समय पर सही रूप में प्राप्त होने पर और प्रयोग में लाने पर ही कार्य करेगी। मैं समझती हूँ कि सिबिल को जानकारी देने और विशेष रूप से कंपनी ऋण के लिए उपलब्ध जानकारी का पूरा उपयोग करने में यह नहीं हो रहा है।
- जबकि बैंकिंग में प्रौद्योगिकी की शुरुआत से सेवा देने की गति और सटीकता में वृद्धि हुई है, इसने साइबर धोखाधड़ियों के प्रति बैंकों की भेद्यता भी बढ़ा दी है। बैंकों द्वारा ऐसी धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए उचित नियंत्रण तंत्र की स्थापना करना आवश्यक है।
- बैंकों के लिए अब यह आवश्यक है कि वे पर्याप्त एमआइएस क्षमता तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी को कोर बैंकिंग समाधान से अधिक ऊंचे स्तर तक ले जाएं। ऐसा होने तक जोखिम प्रबंधन उच्चतम स्तर का नहीं हो सकता और बैंक वित्तीय प्रणाली में बढ़ते परिष्करण की चुनौतियों का सामना का नहीं कर पाएंगे।
- आवास ऋण के क्षेत्र में लुभावने ब्याज दर आना बढ़ रहा है जो कि चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि बैंक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उधारकर्ता ऐसे दरों के प्रभाव को जानते हैं और जब दर सामान्य हो जाते हैं तो मूल्यांकन में उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को ध्यान में लिया जाता है।
- वर्तमान वैश्विक अनुभव ने बैंकों में मजबूत तनाव जांच प्रथाएं आवश्यक कर दी हैं। तनाव जांच से बैंक प्रबंधन सचेत हो जाता है और अनेक प्रकार की जोखिमों संबंधि अनपेक्षित परिणामों को रोका जा सकता है और इस बात का संकेत मिलता है कि हानि के अवशोषण के लिए पूंजी का कितना स्टॉक रखा जाना चाहिए। भारत में, तनाव जांच को मात्र अपेक्षापूर्ति के रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि इसे उचित महत्व देना चाहिए ताकि जोखिम कम की जा

सके या तनाव की स्थिति में प्रासंगिक योजना उपलब्ध रहे।

8. समापन के रूप में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक संकट का ठीक से सामना किया है और यह तेज समावेशक वृद्धि की अपेक्षा पूरी करने में सक्षम है। बासेल के तहत नए प्रतिमा में भी यह प्रणाली पूंजी और चलनिधि के संदर्भ में सुव्यवस्थित है। मजबूत एचआर और जोखिम प्रबंधन की मजबूत प्रथाएं बैंकों को अगले दशक की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएंगी।